पीने के पानी की कमी

711. श्री वे० शि० पाटिल :
श्री ए० बी० पाटिल :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों के कितने गावों मे पीने के पानी की कमी है तथा इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ख) इस समस्या के पूरी तरह से किस वर्ष तक हल हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या LT-282/67]

(ख) देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिये कोई निश्चित अवधि बताना सम्भव नही है क्योंकि यह साधनो की उपलब्धि पर निर्भर करता है । देश के ग्रामीण क्षेत्रो में पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये अनुमानत: 732 करोड रु० की आवश्यकता है जिसके मुकाबिले चौथी योजना अवधि में इस कार्य के लिये अस्थायी रूप से 125 करोड रुपये नियत किये हैं । तथापि यह आशा है कि राज्य और संघ क्षेत्र उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत यथासम्भव ग्रामीण जल संभरण योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे ।

Palai Central Bank

712. Shri Viswambharan: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the dividend so far paid to the depositors of the Palai Central Bank since its liquidation;

(b) whether any dividend has been paid in the last two years; and

(c) the steps Government propose to take to expedite settlement of the claims of the depositors?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Three dividends aggregating Rs. 558.42 lakhs or about 65 per cent of the amounts due to the depositors, have so far been paid by the official liquidator.

(b) No.

(c) The liquidation proceedings are being conducted by the official liquidator under the supervision and directions of the Kerala High Court. The liquidator has filed claims under Section 45D of the Banking Regulation Act, 1949 against all debtors and is making every effort to expedite the recovery of the loans. However, in cases where the Court has granted stay-order or has extended the time for repayment of the debts, it is not possible to expedite further the recovery of the dues.

मध्य प्रदेश में सिन्ध नदी पर बांध

713. श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से सिंचाई प्रायोजना के लिए शिवपुरी जिला (मध्य प्रदेश) में मगरौनी ग्राम के निकट सिन्ध नदी पर एक बांध बनाने की एक योजना उनके मंत्रालय को सरकार की मंजूरी के लिये प्राप्त हुई है;

(ख) इस योजना का काम कब आरम्भ होने की सम्भावना है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस योजना पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है और उससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० ल० राव) (क) और (ख). जी हां; स्कीम की जांच की जा रही है ।